NIOS PYQ's SOLUTIONS

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS & ANSWERS

APRIL-2024

Your Path to Success

खंड - अ

प्रश्न 1 - बाल विवाह एक प्रकार का ऐसा हिन्दू विवाह है जिसमें दुल्हन की आयु

(A) 15 वर्ष न हुई हो

(B) 16 वर्ष न हुई हो

(C) 17 वर्ष न हुई हो

(D) 18 वर्ष न हुई हो

उत्तर – (D) 18 वर्ष न हुई हो

अथवा

मुस्लिम कानून के अन्तर्गत किस निम्नतम आयु का मुसलमान विवाह की संविदा में प्रवेश कर सकता है?

(A) 15 वर्ष

(B) 16 वर्ष

(C) 17 वर्ष

(D) 18 वर्ष

उत्तर – (A) 15 वर्ष

प्रश्न 2 - निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प मुस्लिम कानून का स्रोत नहीं है?

(A) कुरान

(B) श्रुति

(C) सुन्ना

(D) कियास

उत्तर – (B) श्रुति

अथवा

हिन्दू कानून के अन्तर्गत तलाक की किस आधार पर अनुमति नहीं है?

(A) परस्त्रीगमन

(B) पागलपन

(C) स्थानान्तरण

(D) धर्म परिवर्तन

उत्तर – स्थानान्तरण

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 3 - निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प पी०आई०एल० का सही विस्तृत रूप है?

(A) पब्लिक इन्टरेस्ट लॉ

(B) पीपुल इन्टरेस्ट लॉ

(C) पब्लिक इन्फॉर्मेशन लॉ

(D) पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन

उत्तर – (D) पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन

अथवा

निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प सी०पी०सी० का सही विस्तृत रूप है?

(A) सिविल पुलिस कोड

(B) सिविल प्रोसीजर कोड

(C) क्रिमिनल पुलिस कोर्ट

(D) क्रिमिनल प्रोसीजर कोड

उत्तर – (B) सिविल प्रोसीजर कोड

प्रश्न 4 - निम्नलिखित में से कौन-सा एक दण्ड का सिद्धान्त नहीं है?

(A) निवारक सिद्धान्त

(B) अनुनय सिद्धान्त

(C) निरोधात्मक सिद्धान्त

(D) प्रतिकारी सिद्धान्त

उत्तर – (B) अनुनय सिद्धान्त

अथवा

निम्नलिखित में से किस रिट का अर्थ है 'आपका अधिकार क्या है?'

(A) बन्दी प्रत्यक्षीकरण

(B) परमादेश

(C) निषेधादेश

(D) अधिकार-पृच्छा प्रादेश

उत्तर – (D) अधिकार-पृच्छा प्रादेश

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 5 - निम्नलिखित में से कौन-सा विषय/मुद्दा जनहित का नहीं है?

(A) प्रदूषण **(B) आतंकवाद**

(C) कारावास **(D) सड़क सुरक्षा**

उत्तर – (C) कारावास

प्रश्न 6 - भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था?

(A) 2003 **(B) 2004**

(C) 2005 **(D) 2006**

उत्तर – (C) 2005

प्रश्न 7 - निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सार्वजनिक कानून के बारे में सत्य नहीं है?

(A) यह उन मुद्दों के बारे में होता है जो व्यक्ति अथवा राज्य को प्रभावित करते हैं।

(B) सार्वजनिक कानून में राज्य केवल मध्यस्थ ही नहीं होता अपितु एक पार्टी (पक्ष) भी होता है।

(C) सार्वजनिक कानून सरकार के ढाँचे से सम्बन्धित होता है।

(D) सार्वजनिक कानून में राज्य अधिकारों और कर्तव्यों के मध्यस्थ के रूप में उपस्थित रहता है।

उत्तर – (D) सार्वजनिक कानून में राज्य अधिकारों और कर्तव्यों के मध्यस्थ के रूप में उपस्थित रहता है।

अथवा

एक अधिष्ठायी कानून का कार्यक्षेत्र क्या होता है?

(A) प्रजा और राज्य के बीच कानूनी संबंध

(B) दो व्यक्तियों के बीच कानूनी संबंध

(C) दो राज्यों के बीच कानूनी संबंध

(D) संविधान और राज्य के बीच संबंध

उत्तर – (A) प्रजा और राज्य के बीच कानूनी संबंध

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 8 - निम्नलिखित में से कौन-सा एक अधिष्ठायी कानून नहीं है?

(A) दण्ड विधि

(B) प्रक्रियात्मक सिविल कानून

(C) संविदा कानून

(D) सम्पत्ति कानून

उत्तर – (B) प्रक्रियात्मक सिविल कानून

अथवा

निम्नलिखित में से कौन-सा कानून प्रक्रियात्मक कानून नहीं है?

(A) भारतीय साक्ष्य अधिनियम

(B) न्यायालय फीस अधिनियम

(C) वाद मूल्यांकन अधिनियम

(D) विशेष राहत अधिनियम

उत्तर – (D) विशेष राहत अधिनियम

प्रश्न 9 - ए०डी०आर० का सही विस्तृत रूप है

(A) एड्वांस डिस्प्यूट रिजोल्यूशन

(B) ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन

(C) एडवांस डायरेक्ट रिजोल्यूशन

(D) ऐक्टिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन

उत्तर – (B) ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन

अथवा

गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में भारत के कितने राज्य आते हैं?

(A) सात

(B) पाँच

(C) तीन

(D) एक

उत्तर – (A) सात

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 10 -निम्नलिखित में से कौन-सी ए०डी०आर० की तकनीक नहीं है?

(A) विवाचन **(B) लोक अदालत**

(C) मुकदमा **(D) मध्यस्थ विवाचन**

उत्तर – (C) मुकदमा

प्रश्न 11 - मध्यस्थ विवाचन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन विवाद समाधान में सहायता करता है?

(A) लोक अदालत **(B) कोई तीसरा व्यक्ति**

(C) मजिस्ट्रेट **(D) वकील**

उत्तर – (B) कोई तीसरा व्यक्ति

अथवा

'मध्यस्थता' की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन विवाद समाधान में सहायता करता है?

(A) जिला न्यायालय **(B) कोई स्वतंत्र तीसरा व्यक्ति**

(C) जिला मजिस्ट्रेट **(D) लोक अदालत**

उत्तर – (B) कोई स्वतंत्र तीसरा व्यक्ति

प्रश्न 12 - प्रारम्भ में लोक अदालत के कैम्प किस राज्य में शुरू किए गए थे?

(A) दिल्ली **(B) पंजाब**

(C) बिहार **(D) गुजरात**

उत्तर – (D) गुजरात

प्रश्न 13 - निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है?

(A) प्रभुत्व सम्पन्न **(B) राष्ट्रीय**

(C) पंथनिरपेक्ष **(D) गणतंत्र**

उत्तर – (B) राष्ट्रीय

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

अथवा

संविधान समिति ने संविधान को कब अंगीकार किया था ?

(A) 26 नवम्बर, 1949 **(B) 26 जनवरी, 1950**

(C) 26 नवम्बर, 1950 **(D) 26 जनवरी, 1949**

उत्तर – (A) 26 नवम्बर, 1949

प्रश्न 14 - भारतीय संविधान की प्रस्तावना

(A) संविधान के प्रारम्भ में है

(B) संविधान के अन्त में है

(C) संविधान में नहीं दी गई है

(D) संविधान के मध्य में है

उत्तर – (A) संविधान के प्रारम्भ में है

अथवा

निम्नलिखित में से संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था ?

(A) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद **(B) डॉ० बी० आर० अम्बेडकर**

(C) महात्मा गाँधी **(D) जवाहरलाल नेहरू**

उत्तर – (A) डॉ० राजेन्द्र प्रसाद

प्रश्न 15 - वर्तमान में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं?

(A) चार **(B) पाँच**

(C) छः **(D) सात**

उत्तर – (C) छः

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 16 - स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अन्तर्गत कितनी स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई हैं?

(A) पाँच **(B) छः**

(C) सात **(D) आठ**

उत्तर - (B) छः

प्रश्न 17 – राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?

(A) 25 वर्ष **(B) 28 वर्ष**

(C) 30 वर्ष **(D) 35 वर्ष**

उत्तर – (C) 30 वर्ष

प्रश्न 18 - निम्नलिखित में से किस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है?

(A) उत्तर प्रदेश **(B) पश्चिम बंगाल**

(C) तमिलनाडु **(D) आन्ध्र प्रदेश**

उत्तर – (A) उत्तर प्रदेश

प्रश्न 19 - निम्नलिखित में से किस एक का प्रयोग केवल लोकसभा के सदस्य ही कर सकते हैं?

(A) स्थगन प्रस्ताव **(B) प्रश्न काल**

(C) ध्यानाकर्षण प्रस्ताव **(D) अविश्वास प्रस्ताव**

उत्तर - (D) अविश्वास प्रस्ताव

प्रश्न 20 - भारत के सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल कितने न्यायाधीश हैं?

(A) 25 **(B) 27**

(C) 29 **(D) 31**

उत्तर – (D) 31

प्रश्न 21 - रिक्त स्थानों को ठीक से भरिए :

मुस्लिम कानून के अन्तर्गत एक पति अपनी ____ को बिना कोई ____ बताए विवाह का खण्डन करके तलाक दे सकता है।

उत्तर – पत्नी, कारण

अथवा

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

हिन्दू विवाह अधिनियम ____ तथा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम ____ हिन्दू कानून के दो प्रमुख अधिनियम है।

उत्तर – 1955, 1956

प्रश्न 22 - निम्नलिखित में से किन्हीं दो का सही मिलान कीजिए :

कॉलम-A	**कॉलम-B**
(a) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925	**(i) हिन्दू विवाह अधिनियम**
(b) सपिंड	**(ii) ईसाई**
(c) कियास	**(iii) मुस्लिम कानून का स्रोत**
(d) निर्वसीयत उत्तराधिकार	**(iv) हिन्दू कानून**

उत्तर – (a) भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 - (ii) ईसाई

(b) सपिंड - (i) हिन्दू विवाह अधिनियम

(c) कियास - (iii) मुस्लिम कानून का स्रोत

(d) निर्वसीयत उत्तराधिकार - (iv) हिन्दू कानून

प्रश्न 23 - किन्हीं दो कथनों के बारे में 'सत्य' अथवा 'असत्य' लिखिए :

(क) न्यायाधीश कोई नया कानून बना सकते हैं।

उत्तर – असत्य

(ख) प्रशासन को राजनीतिक शक्तियों के प्रयोग के रूप में परिभाषित किया गया है।

उत्तर – असत्य

(ग) संविधान के अनुसार, भारत एक पूँजीवाद देश है।

उत्तर – असत्य

(घ) निजी कानून, नागरिकों के एक-दूसरे के साथ सम्बन्धों को शासित करता है।

उत्तर – सत्य

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 24 - रिक्त स्थानों को ठीक से भरिए :

आपराधिक कानून, ____ का वह निकाय है जो ____ से सम्बन्धित है।

उत्तर – कानून, अपराध

अथवा

प्रशासनिक कानून को ____ एजेन्सियों ने विनियमों और ____ के रूप में निर्मित किया है।

उत्तर – प्रशासनिक, आदेशों

प्रश्न 25 - निम्नलिखित कथनों के बारे में 'सत्य' अथवा 'असत्य' लिखें (कोई दो) :

(क) अपील का अधिकार अधिष्ठायी कानून है।

उत्तर – असत्य

(ख) अधिष्ठायी कानून ऐसे नियम बनाता है जिसकी सहायता से कानून लागू किया जाता है।

उत्तर – असत्य

(ग) प्रक्रियात्मक कानून को कानून की उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो मुकदमेबाजी की प्रक्रिया को नियन्त्रित करता है।

उत्तर – सत्य

(घ) प्रक्रियात्मक कानून में सभी कानूनी कार्यवाहियाँ, सिविल अथवा आपराधिक, शामिल होती हैं।

उत्तर – सत्य

प्रश्न 26 - निम्नलिखित कथनों के बारे में सत्य अथवा असत्य लिखिए :

(क) अधिष्ठायी और प्रक्रियात्मक कानून के बीच अन्तर तथ्यात्मक और वास्तविक होता है।

उत्तर – सत्य

(ख) अधिष्ठायी कानून सांविधानिक कानून है जो अपराध अथवा गलत कार्य एवं उसके उपचार परिभाषित करता है।

उत्तर – सत्य

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 27 - निम्नलिखित में किन्हीं दो कथनों के बारे में 'सत्य' अथवा 'असत्य' लिखिए :

(क) लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान (ए०डी०आर०) की सबसे लोकप्रिय तकनीक है।

उत्तर – सत्य

(ख) लोक अदालत की कोई कानूनी हैसियत नहीं है।

उत्तर – असत्य

(ग) लोक अदालतों के निर्णयों को किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

उत्तर – सत्य

(घ) लोक अदालतें तीव्र और सस्ता न्याय प्रदान करती हैं।

उत्तर – सत्य

प्रश्न 28 - निम्नलिखित में किन्हीं दो कथनों के बारे में 'सत्य' अथवा 'असत्य' लिखिए :

(क) कानूनी अधिकारों और संवैधानिक अधिकारों के बीच कोई अन्तर नहीं है।

उत्तर – असत्य

(ख) सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति दी गई है।

उत्तर – सत्य

(ग) केशवानन्द भारती केस के अनुसार संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है।

उत्तर – सत्य

(घ) 42वें संविधान संशोधन ने मौलिक अधिकारों को संशोधित करने के संसद के अधिकार पर जोर दिया है।

उत्तर – सत्य

प्रश्न 29 - रिक्त स्थानों को ठीक से भरिये (कोई एक) :

(क) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह ____ का पालन करे और इसके ____ का आदर करे।

उत्तर – संविधान, आदर्शों

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(ख) मौलिक अधिकारों के पीछे ____ की शक्ति होती है और ____ के पीछे जनमत की शक्ति होती है।

उत्तर – कानूनी, नीति निर्देशक सिद्धान्तों

प्रश्न 30 - रिक्त स्थानों को ठीक से भरिए :

भारत में ____ के चुनाव के लिए लोकसभा के सदस्य चुनाव ____ का एक भाग होते हैं।

उत्तर – राष्ट्रपति, मंडल

अथवा

विधान ____ के सदस्यों को विधानसभा के ____ छः वर्ष के लिए निर्वाचित करते हैं।

उत्तर – परिषद, सदस्य

प्रश्न 31 - भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से ____ की प्रक्रिया के माध्यम से ____ जा सकता है।

उत्तर – महाभियोग, हटाया

प्रश्न 32 - भारत में अपनायी गई ____ व्यवस्था न्यायालयों की ____ पर आधारित है।

उत्तर – न्यायिक व्यवस्था, एक श्रृंखला (पदसोपन)

प्रश्न 33 - 'न्यायिक सक्रियता' शब्दावली का प्रयोग ____ द्वारा नीतियाँ शुरू करके ____ प्रदान करने की भूमिका के लिए किया जाता है।

उत्तर – न्यायपालिका, न्याय

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 34 - रिक्त स्थानों को ठीक से भरिए :

1984 की ____ गैस त्रासदी के बाद ____ सक्रियता में वृद्धि हुई जिसने वर्तमान कानूनों की पुनर्व्याख्या का मार्ग प्रशस्त किया।

उत्तर – भोपाल, न्यायिक

अथवा

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

इलेक्ट्रिसिटी (बिजली) अधिनियम, 2003 ने ____ क्षेत्र में बेहतर विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया और ____ ऊर्जा प्रयोग करने पर बल दिया।

उत्तर – विद्युत, नवीकरणीय

प्रश्न 35 - निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए (कोई दो) :

कॉलम-A	**कॉलम-B**
(a) क्योटो प्रोटोकोल	**(i) ओजोन परत को बचाना**
(b) वियना सम्मेलन	**(ii) 2010**
(c) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम	**(iii) 1981**
(d) नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल	**(iv) ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन**

उत्तर – (a) क्योटो प्रोटोकोल - (iv) ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन

(b) वियना सम्मेलन - (i) ओजोन परत को बचाना

(c) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम - (iii) 1981

(d) नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल - (ii) 2010

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 34 - निम्नलिखित में से किन्हीं दो का सही विस्तृत रूप लिखिए :

(क) सी०सी०आई० **(ख) एम०आर०टी०पी०**

(ग) एन०सी०डी०आर०सी० **(घ) सी०पी०ए०**

उत्तर – (क) सी०सी०आई० (CCI) - भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

(ख) एम०आर०टी०पी० (MRTP) - एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार

(ग) एन०सी०डी०आर०सी० (NCDRC) - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग

(घ) सी०पी०ए० (CPA) - उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

प्रश्न 35 - निम्नलिखित कथनों के बारे में सही अथवा गलत लिखिए :

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(क) उपभोक्ता सक्रियता का मुख्य उद्देश्य है कि राज्य को अनुचित कारोबारी व्यवहारों के विरुद्ध उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

उत्तर – सत्य

(ख) निवारण का अर्थ है उपभोक्ता के लिए उपचार प्रदान करना।

उत्तर – सत्य

खण्ड-ख

प्रश्न 36 - 'निजी कानून' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – निजी कानून, कानूनों का वह समूह है जो व्यक्ति के धर्म, जाति या समुदाय पर आधारित होता है। यह लोगों के निजी मामलों जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और भरण-पोषण को नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए, हिंदुओं के लिए हिंदू कानून और मुसलमानों के लिए मुस्लिम कानून लागू होता है।

अथवा

'मिश्रित कानूनी व्यवस्था' की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – मिश्रित कानूनी व्यवस्था वह प्रणाली है, जिसमें दो या अधिक प्रकार की कानूनी परंपराओं का मिश्रण होता है। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहाँ सामान्य कानून , संहिताबद्ध कानून और विभिन्न धर्मों के निजी कानून एक साथ कार्य करते हैं।

प्रश्न 37 - 'प्रारूपण' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – प्रारूपण का अर्थ कानूनी दस्तावेजों को तैयार करना और लिखना है। यह वसीयत, अनुबंध, शपथ पत्र या अन्य कानूनी कागजात को सही कानूनी भाषा में लिखित रूप देने की कला है, ताकि भविष्य में तथ्यों को लेकर कोई भ्रम या विवाद न हो।

अथवा

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

'अभिवाचन' की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – अभिवाचन वे औपचारिक लिखित बयान होते हैं, जिन्हें वादी और प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें वाद पत्र तथा लिखित कथन शामिल होते हैं, जिनके माध्यम से दोनों पक्ष अपने-अपने दावों और मामले से जुड़े तथ्यों को स्पष्ट रूप से न्यायालय के समक्ष रखते हैं।

प्रश्न 38 - 'एक्टस रीयस' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – '**एक्टस रीयस**' एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ **दोषपूर्ण** या **अपराधपूर्ण कार्य** होता है, जो किसी भौतिक घटना के रूप में प्रकट होती है। इसमें केवल वही कार्य या चूक शामिल होती है, जो जानबूझकर और स्वेच्छा से किए गए हों।

अथवा

आपराधिक कानून में 'नशा' को प्रतिरक्षा के रूप में स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – भारतीय दंड संहिता के अनुसार, नशा तब एक वैध प्रतिरक्षा माना जाता है जब वह आरोपी की इच्छा के विरुद्ध या धोखे से कराया गया हो। यदि नशे की अवस्था में आरोपी अपने किए गए कार्य की प्रकृति को समझने में असमर्थ था, तो उसे अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाता।

प्रश्न 39 - 'प्रक्रियात्मक कानून' के अर्थ को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – प्रक्रियात्मक कानून वह विधि है, जो यह निर्धारित करती है कि मौलिक अथवा अधिष्ठायी कानूनों को व्यवहार में कैसे लागू किया जाए। यह अदालतों में मुकदमा दायर करने, जांच करने, साक्ष्य प्रस्तुत करने तथा निर्णय देने की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जैसे दंड प्रक्रिया संहिता और दीवानी प्रक्रिया संहिता।

अथवा

'प्रशासनिक कानून' के अर्थ को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – प्रशासनिक कानून सार्वजनिक कानून की वह शाखा है, जो सरकार की प्रशासनिक एजेंसियों (कार्यपालिका) की शक्तियों, कार्यों और दायित्वों को नियंत्रित करती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रशासन अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न करे तथा नागरिकों के अधिकारों की प्रभावी रक्षा हो।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 40 - 'शोषण के विरुद्ध अधिकार' मौलिक अधिकार की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – संविधान के **अनुच्छेद 23** और **24** में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किया गया है। यह मानव तस्करी, बेगार तथा बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है। साथ ही, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खदानों और अन्य खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर प्रतिबंध करता है।

अथवा

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों (DPSP) का मुख्य उद्देश्य भारत को एक '**लोक कल्याणकारी राज्य**' बनाना है। इनका उद्देश्य देश में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, जिससे सभी नागरिकों को न्याय, समान अवसर और बेहतर जीवन स्तर मिल सके।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 41 - स्टाकहोम उद्घोषणा, 1972 के किन्हीं दो प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – स्टाकहोम उद्घोषणा (1972) के दो मुख्य प्रावधान :

1. संसाधनों का संरक्षण : पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों जैसे हवा, पानी, भूमि और वनस्पति का संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि उन्हें वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जा सके।

2. प्रदूषण नियंत्रण : विषाक्त पदार्थों और गर्मी का उत्सर्जन उस मात्रा से अधिक नहीं होना चाहिए जिसे पर्यावरण सहन न कर सके।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 41 - 'उपभोक्ता निवारण' पद का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – उपभोक्ता निवारण का अर्थ उपभोक्ताओं की शिकायतों या समस्याओं का कानूनी समाधान करना है। यदि किसी उपभोक्ता को खराब उत्पाद या सेवा के कारण नुकसान हुआ है, तो उसे उचित मुआवजा, वस्तु की मरम्मत या प्रतिस्थापन प्रदान करना ही निवारण कहलाता है।

प्रश्न 42 - मुस्लिम कानून के अन्तर्गत एक वैध विवाह की किन्हीं चार अनिवार्यताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर – मुस्लिम कानून के अंतर्गत वैध विवाह (निकाह) की चार अनिवार्यताएँ :

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

1. **प्रस्ताव और स्वीकृति :** एक पक्ष द्वारा विवाह का प्रस्ताव और दूसरे पक्ष द्वारा उसी बैठक में उसकी स्वीकृति आवश्यक है।
2. **सक्षमता :** वर और वधू दोनों का वयस्क (15 वर्ष की आयु) और स्वस्थ मस्तिष्क का होना अनिवार्य है।
3. **स्वतंत्र सहमति :** विवाह के लिए सहमति बिना किसी दबाव, कपट या जोर-जबरदस्ती के होनी चाहिए।
4. **गवाह :** विवाह के समय दो पुरुष या एक पुरुष और दो महिला गवाहों की उपस्थिति आवश्यक है।

अथवा

हिन्दू कानून के अन्तर्गत एक वैध विवाह की किन्हीं चार अनिवार्यताओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर – हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार वैध विवाह की चार अनिवार्यताएँ :

1. **एकविवाह :** विवाह के समय किसी भी पक्ष का पति या पत्नी जीवित नहीं होना चाहिए।
2. **मानसिक स्थिति :** दोनों पक्ष विवाह के लिए वैध सहमति देने में सक्षम हों और मानसिक रूप से स्वस्थ हों।
3. **आयु सीमा :** वर की आयु 21 वर्ष और वधू की आयु 18 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
4. **निषिद्ध रिश्ते :** दोनों पक्ष निषिद्ध रिश्तों जैसे भाई-बहन या निकट संबंधों के दायरे में नहीं आने चाहिए, जब तक कि उनकी प्रथा इसकी अनुमति न दे।

प्रश्न 43 - दण्ड के 'सुधारात्मक सिद्धान्त' का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – सुधारात्मक सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को दण्ड देने के बजाय उसके स्वभाव और आचरण को सही दिशा में बदलना ही इसका मूल विचार है।

1. मुख्य उद्देश्य : इस सिद्धान्त का उद्देश्य अपराधी को कष्ट देना नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और चरित्र में सुधार लाना है, ताकि वह भविष्य में अपराध न करे।

2. सुधार की प्रक्रिया : इसके अंतर्गत अपराधियों को शिक्षा, प्रशिक्षण और नैतिक मार्गदर्शन दिया जाता है, जिससे वे समाज के उपयोगी नागरिक बन सकें।

3. उपयोगिता : यह सिद्धान्त विशेष रूप से किशोर और पहली बार अपराध करने वालों के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है, ताकि उन्हें पक्का अपराधी बनने से रोका जा सके।

अथवा

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

दण्ड के 'प्रतिकारी सिद्धान्त' का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – प्रतिकारी सिद्धान्त के अनुसार अपराधी को दण्ड इसलिए दिया जाता है, ताकि उसे उसके किए गए अपराध का प्रतिशोध मिले।

1. **मुख्य उद्देश्य :** इस सिद्धान्त का उद्देश्य अपराधी को उसके अपराध का बदला देना है, ताकि न्याय की भावना संतुष्ट हो सके।
2. **भय उत्पन्न करना :** कठोर दण्ड के माध्यम से समाज में भय पैदा किया जाता है, जिससे अन्य लोग अपराध करने से बचें।
3. **आधुनिक दृष्टिकोण :** आधुनिक समय में इस सिद्धान्त को कठोर और अमानवीय माना जाता है, क्योंकि यह अपराधी के सुधार पर ध्यान नहीं देता।

प्रश्न 44 - संघीय कानूनों का आधिपत्य और राज्य द्वारा निर्मित सीमाबद्धताओं का आकलन कीजिए।

उत्तर – संघीय कानूनों का आधिपत्य और राज्य की सीमाएँ :

1. **विधायी शक्तियों का विभाजन :** भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें संघीय कानूनों को अधिक महत्व दिया गया है।
2. **संघीय कानूनों की सर्वोच्चता :** समवर्ती सूची के किसी विषय पर यदि राज्य और केंद्र के कानूनों में टकराव हो, तो केंद्रीय कानून ही प्रभावी माना जाता है।
3. **राज्य की सीमाएँ :** राज्य विधानसभाएँ केवल राज्य सूची के विषयों पर और अपने क्षेत्र तक ही कानून बना सकती हैं। वे संघ सूची के विषयों पर कानून नहीं बना सकतीं।
4. **अवशिष्ट शक्तियाँ :** जो विषय किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है।

अथवा

दण्ड के किन्हीं दो सिद्धांतों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – दण्ड के दो सिद्धांत :

1. निवारक सिद्धान्त : इस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य यह सिद्ध करना है कि 'अपराध करना अपराधी के लिए एक गलत सौदा है'।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

- **दण्ड का स्वरूप :** इस सिद्धान्त के समर्थक कठोर दण्ड जैसे प्राणदण्ड आदि के पक्षधर होते हैं, जिससे अपराध को निरर्थक सिद्ध किया जा सके।

2. निरोधक सिद्धान्त : इस सिद्धान्त का उद्देश्य अपराधी को पुनः अपराध करने से रोकना या उसे अक्षम बना देना है।

- **दंड का स्वरूप :** इसके समर्थक अपराधी को समाज से अलग रखने के लिए कारावास या जुर्माना लगाने की वकालत करते हैं।

प्रश्न 45 – लोगों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को प्राप्त करने के एक साधन के रूप में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाने का लक्ष्य रखते हैं। यद्यपि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, फिर भी शासन के लिए मूलभूत मार्गदर्शक हैं।

1. **आजीविका का अधिकार :** ये सिद्धान्त राज्य को सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।
2. **समानता और न्याय :** इनके अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है।
3. **आर्थिक संतुलन :** ये सिद्धान्त धन के केंद्रीकरण को रोकने और संसाधनों के न्यायसंगत वितरण को बढ़ावा देते हैं।

अथवा

1976 में भारत के संविधान में जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों के महत्त्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – 42वें संशोधन संशोधन 1976 द्वारा संविधान के भाग IV-A (अनुच्छेद 51A) में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। इनका महत्त्व इस प्रकार है :

1. संतुलन : ये अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाते हैं; नागरिक केवल अधिकारों का आनंद नहीं ले सकते, उन्हें देश के प्रति जिम्मेदार भी होना चाहिए।

2. नागरिक चेतना : ये नागरिकों को संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं।

3. समाज और राष्ट्र सेवा : मौलिक कर्तव्य भारत की संप्रभुता की रक्षा, आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण पर बल देते हैं।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 46 - नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की किन्हीं चार शक्तियों को उजागर कीजिए।

उत्तर – नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की चार प्रमुख शक्तियाँ :

1. **मुआवजा दिलाना :** यह प्रदूषण या पर्यावरणीय दुर्घटनाओं से प्रभावित पीड़ितों को आर्थिक मुआवजा और राहत देने का आदेश दे सकता है।
2. **संपत्ति की बहाली :** यह क्षतिग्रस्त पर्यावरण या संपत्ति को पूर्ववत स्थिति में लाने का आदेश दे सकता है।
3. **सिविल कोर्ट की शक्ति :** इसे गवाहों को बुलाने और दस्तावेजों की मांग करने के लिए सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां प्राप्त हैं।
4. **त्वरित न्याय :** इसे मामलों का निपटारा याचिका दायर करने के 6 महीने के भीतर करना होता है।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 46 - किन्हीं चार अनुचित कारोबारी व्यवहारों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत चार अनुचित कारोबारी व्यवहार :

1. **झूठा प्रतिनिधित्व :** किसी उत्पाद की गुणवत्ता, मानक या ग्रेड के बारे में गलत दावा करना अथवा पुराने माल को नया बताकर बेचना।
2. **भ्रामक विज्ञापन :** वस्तुओं या सेवाओं के बारे में झूठे या भ्रामक विज्ञापन देना, जैसे "मुफ़्त उपहार" का लालच देना जबकि उसका मूल्य पहले ही वसूल लिया गया हो।
3. **जमाखोरी :** कीमतों को कृत्रिम रूप से बढ़ाने के उद्देश्य से वस्तुओं को छिपाकर रखना या नष्ट करना।
4. **सुरक्षा मानकों की अनदेखी :** ऐसे उत्पाद बेचना जो निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करते और उपभोक्ताओं के जीवन या स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकते हैं।

प्रश्न 47 - 'प्ली बार्गेनिंग' का अर्थ एवं इसके कोई दो प्रकार स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – जब किसी आरोपी द्वारा अपना अपराध स्वीकार कर लिया जाता है और न्यायालय उस स्वीकारोक्ति को स्वीकार कर लेता है, तो इसे प्ली बार्गेनिंग कहा जाता है। इसमें आरोपी और अभियोजन पक्ष के बीच समझौता होता है, जिससे मुकदमे का जल्दी निपटारा हो जाता है और न्यायालय का समय बचता है।

प्ली बार्गेनिंग के दो प्रकार :

1. आरोप (चार्ज) बार्गेनिंग : यह प्ली बार्गेनिंग का सबसे सामान्य रूप है। इसमें आरोपी व्यक्ति अपने विरुद्ध लगे आरोपों पर समझौता करता है। यदि वह अपराध स्वीकार कर लेता है, तो अभियोजक गंभीर या अनेक

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

आरोपों को हटा देता है। उदाहरण के लिए, हत्या के प्रथम श्रेणी के आरोप को हटाकर कम गंभीर अपराध को स्वीकार किया जा सकता है।

2. दण्ड बार्गेनिंग : इसमें आरोपी व्यक्ति कम या हल्की सजा पाने के लिए अपना अपराध स्वीकार करता है। इससे अभियोजन पक्ष को मुकदमे की लंबी प्रक्रिया और अपराध सिद्ध करने की आवश्यकता से राहत मिलती है, तथा आरोपी को कम दण्ड का लाभ मिलता है।

अथवा

विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 1994 के किन्हीं तीन प्रमुख प्रावधानों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – विधिक सेवाएँ प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 1994 के तीन प्रमुख प्रावधान :

1. निःशुल्क कानूनी सहायता : इस अधिनियम के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएँ, बच्चे, दिव्यांग व्यक्ति तथा कम आय वाले लोगों को निःशुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, ताकि आर्थिक कठिनाइयों के कारण कोई भी व्यक्ति न्याय से वंचित न रहे।

2. लोक अदालतों का गठन : इस अधिनियम द्वारा लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। लोक अदालतों के निर्णय अंतिम होते हैं तथा वे दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, जिससे मामलों का शीघ्र और सरल निपटारा होता है।

3. विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना : इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना की गई है। ये प्राधिकरण कानूनी जागरूकता फैलाने, निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने और लोक अदालतों के आयोजन का कार्य करते हैं।

प्रश्न 48 - भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों के महत्त्व का आकलन कीजिए।

उत्तर – भारत के संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों का महत्त्व :

1. व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा : मौलिक अधिकार व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और अभिव्यक्ति की आज़ादी प्रदान करते हैं, जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन जी सके।

2. समानता का सिद्धांत : ये अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करते हैं और जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकते हैं।

3. लोकतंत्र की मजबूती : मौलिक अधिकार नागरिकों को सरकार की मनमानी के विरुद्ध संरक्षण देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

4. न्यायिक संरक्षण : इन अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं, जिससे अधिकारों की प्रभावी रक्षा होती है।

5. सामाजिक न्याय की स्थापना : मौलिक अधिकार कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा कर सामाजिक न्याय और समान अवसर को बढ़ावा देते हैं।

6. नागरिक चेतना का विकास : ये अधिकार नागरिकों में अधिकार-बोध और जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं।

अथवा

संविधान की कार्यप्रणाली में प्रस्तावना की भूमिका का आकलन कीजिए।

उत्तर – संविधान की कार्यप्रणाली में प्रस्तावना की भूमिका :

1. संविधान का दर्पण और आत्मा : प्रस्तावना भारतीय संविधान का दर्पण और आत्मा है, क्योंकि इसमें संविधान के मूल आदर्श और उद्देश्य निहित हैं।

2. व्याख्या में सहायक : जब संविधान के किसी अनुच्छेद का अर्थ अस्पष्ट होता है, तब न्यायपालिका उसकी सही व्याख्या के लिए प्रस्तावना का सहारा लेती है।

3. सरकार के लिए मार्गदर्शक : प्रस्तावना सरकार को यह निर्देश देती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है तथा उसका लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है।

4. संविधान की कसौटी : केशवानंद भारती मामले के अनुसार प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और इसके मूल ढाँचे को बदला नहीं जा सकता।

5. राष्ट्रीय एकता : यह नागरिकों में एकता और अखंडता की भावना को सुदृढ़ करती है।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7A

प्रश्न 49 - धारणीय विकास की आवश्यकता के किन्हीं तीन कारणों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – धारणीय विकास की आवश्यकता के मुख्य तीन कारण :

1. **संसाधनों का संरक्षण :** पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन जैसे- जल, खनिज, वन सीमित हैं। यदि हम वर्तमान में इनका अंधाधुंध दोहन करेंगे, तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। धारणीय विकास इन संसाधनों के विवेकपूर्ण और संतुलित उपयोग को सुनिश्चित करता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

2. **पर्यावरण संरक्षण :** तीव्र औद्योगीकरण और विकास के कारण पर्यावरण को भारी क्षति पहुँच रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। धारणीय विकास यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक प्रगति के साथ-साथ पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे।
3. **भावी पीढ़ियों की सुरक्षा :** धारणीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारण अंतर-पीढ़ीगत समता है, जिसके अनुसार हमें अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को इस प्रकार पूरा करना चाहिए कि भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रहें और वे अपने जीवन तथा अस्तित्व को बनाए रख सकें।

अथवा

'पर्यावरण के संरक्षण' के पक्ष में किन्हीं दो न्यायिक निर्णयों के उदाहरण उजागर कीजिए।

उत्तर – पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में भारतीय न्यायपालिका ने कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिनमें से दो प्रमुख उदाहरण इस प्रकार है :

1. एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (गंगा प्रदूषण मामला)

- **समस्या :** यह मामला गंगा नदी में बढ़ते प्रदूषण से संबंधित था। कानपुर और आसपास के शहरों के चमड़ा उद्योग अपना बिना उपचारित गंदा और रासायनिक पानी सीधे गंगा नदी में बहा रहे थे।
- **न्यायालय का निर्णय :** सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में कठोर रुख अपनाते हुए आदेश दिया कि कोई भी उद्योग बिना जल शोधन संयंत्र लगाए अपना कचरा नदी में नहीं बहा सकता।

2. रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटेलमेंट केंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (देहरादून खदान मामला)

- **समस्या :** यह मामला देहरादून और मसूरी की घाटियों में चल रही चूना-पत्थर की खदानों से संबंधित था। इन खदानों से उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी और पर्यावरण संतुलन नष्ट हो रहा था।
- **न्यायालय का निर्णय :** सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देते हुए इन खदानों को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया।

वैकल्पिक मॉड्यूल-7B

प्रश्न 49 - अनुचित कारोबारी व्यवहारों के विरुद्ध निवारण के किन्हीं दो प्रावधानों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत '**अनुचित कारोबारी व्यवहार**' जैसे-भ्रामक विज्ञापन, जमाखोरी, या खराब गुणवत्ता वाली वस्तुओं की बिक्री के विरुद्ध निवारण के लिए दो मुख्य प्रावधान इस प्रकार किए गए हैं :

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

1. त्रि-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र : उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तीन स्तरों पर विशेष अदालतें बनाई गई हैं :

- **जिला आयोग :** जिला स्तर पर उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई करता है और उनका निपटारा करता है।
- **राज्य आयोग :** राज्य स्तर पर कार्य करता है, जहाँ जिला आयोग के फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकती है।
- **राष्ट्रीय आयोग :** राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च उपभोक्ता आयोग है, जो राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध अपीलों पर निर्णय देता है।

2. उपचारात्मक आदेश : यदि उपभोक्ता की शिकायत सही पाई जाती है, तो उपभोक्ता आयोग व्यापारी या सेवा प्रदाता को एक या अधिक आदेश दे सकता है, जैसे :

- वस्तु में पाई गई खराबी को दूर करने का आदेश देना।
- दोषपूर्ण वस्तु को नई और सही वस्तु से बदलने का निर्देश देना।
- उपभोक्ता द्वारा चुकाई गई पूरी या आंशिक राशि वापस करने का आदेश देना।

अथवा

भारत में उपभोक्ता आंदोलन के प्रभाव का आकलन कीजिए।

उत्तर – भारत में उपभोक्ता आंदोलन के प्रभाव :

1. **कानूनी सशक्तिकरण :** इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। इस अधिनियम ने उपभोक्ताओं को कानूनी अधिकार प्रदान किए और घटिया वस्तुओं तथा अनुचित व्यापारिक प्रथाओं के विरुद्ध न्याय पाने का प्रभावी मंच दिया।
2. **जागरूकता और शिक्षा :** मीडिया, जनहित याचिकाओं और विभिन्न अभियानों के माध्यम से उपभोक्ताओं में अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ी है।
3. **शिकायत निवारण तंत्र :** उपभोक्ताओं को त्वरित और सस्ता न्याय देने के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर त्रि-स्तरीय उपभोक्ता आयोगों की स्थापना की गई है।
4. **बाजार में संतुलन और जवाबदेही :** इस आंदोलन के कारण व्यापारियों को उपभोक्ताओं के प्रति अधिक जिम्मेदार होना पड़ा है, जिससे मिलावट, जमाखोरी और भ्रामक विज्ञापनों पर नियंत्रण हुआ है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

5. **उपभोक्ता संगठनों का विकास :** देश में अनेक उपभोक्ता संगठन सक्रिय हुए हैं, जो उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन और कानूनी सहायता प्रदान करते हैं।
6. **डिजिटल युग के अनुकूलन :** ई-दाखिल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से उपभोक्ता घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

NIOS PYQ's SOLUTIONS

PREVIOUS YEARS' QUESTIONS & ANSWERS

OCTOBER-2024

Your Path to Success

खंड – क

प्रश्न 1 – मानव आचरण के मार्गदर्शक के रूप में कानून की अवधारणा निम्नलिखित में से किस के अस्तित्व जितनी पुरानी है ?

(A) मानव उत्पत्ति **(B) सभ्य समाज**

(C) सरकार **(D) अदालतों**

उत्तर - (B) सभ्य समाज

प्रश्न 2 – निजी कानून निम्नलिखित में से किस के साथ नागरिकों के सम्बन्धों को विनियमित और शासित करते हैं?

(A) सरकार **(B) समाज**

(C) आपस में एक दूसरे के साथ **(D) प्राईवेट कम्पनियों के साथ**

उत्तर - (C) आपस में एक दूसरे के साथ

प्रश्न 3 – व्यक्तिगत कानून निम्नलिखित में से किस का निपटारा नहीं करता है?

(A) विवाह **(B) तलाक**

(C) उत्तराधिकार **(D) रोजगार**

उत्तर - (D) रोजगार

प्रश्न 4 – निम्नलिखित में से कौन हिन्दु कानून का स्त्रोत नहीं है?

(A) रीति-रिवाज **(B) वेद**

(C) हिन्दुओं के बारे में न्यायिक निर्णय **(D) अन्तर्राष्ट्रीय कानून**

उत्तर - (D) अन्तर्राष्ट्रीय कानून

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 5 – 16वीं शताब्दी में भारत के पश्चिमी भागों में रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी ?

(A) पारसियों

(B) पुर्तगालियों

(C) फ्रांसीसियों

(D) यहूदियों

उत्तर - (B) पुर्तगालियों

प्रश्न 6 – भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम किस वर्ष संहिताबद्ध किया गया था?

(A) 1870

(B) 1872

(C) 1874

(D) 1876

उत्तर - (B) 1872

प्रश्न 7 – दण्ड का कौन सा सिद्धान्त दूसरों को सबक सिखाने के लिए 'फांसी की सज़ा' देने की वकालत करता है?

(A) सुधारात्मक सिद्धान्त

(B) निवारक सिद्धान्त

(C) प्रतिकारी सिद्धान्त

(D) क्षतिपूर्ति सिद्धान्त

उत्तर - (B) निवारक सिद्धान्त

प्रश्न 8 – आई.पी.सी. (IPC) का सही विस्तृत रूप चुनिए :

(A) इन्डियन पर्सनल कोड

(B) इन्डियन पर्सनल कन्डक्ट

(C) इन्डियन पीनल कोड

(D) इन्डियन पीनल केस

उत्तर - (C) इन्डियन पीनल कोड

प्रश्न 9 – दण्ड का कौन सा सिद्धान्त 'आप हत्या द्वारा उपचार नहीं कर सकते' की उक्ति पर आधारित है?

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

A) निवारक सिद्धान्त **(B) सुधारात्मक सिद्धान्त**

C) निरोधक सिद्धान्त **(D) क्षतिपूर्ति सिद्धान्त**

उत्तर - (B) सुधारात्मक सिद्धान्त

प्रश्न 10 – निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवाचन (pleading) के बारे में 'सत्य' है?

(A) प्रत्येक अभिवाचन में कानूनों का उल्लेख होना चाहिए।

(B) प्रत्येक अभिवाचन में तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए।

(C) प्रत्येक अभिवाचन मौखिक होना चाहिए।

(D) प्रत्येक अभिवाचन दण्ड कम करने के लिए है।

उत्तर - (B) प्रत्येक अभिवाचन में तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए।

प्रश्न 11 –निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 'संवैधानिक उपचारों के अधिकार' के अन्तर्गत नहीं आता ?

(A) बंदी प्रत्यक्षीकरण **(B) परमादेश**

(C) निषेधादेश **(D) रियायत**

उत्तर - (D) रियायत

प्रश्न 12 – 'सूचना का अधिकार' का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस को सूचना प्रदान करने का है?

(A) प्रेस **(B) नागरिकों**

(C) अदालतों **(D) वकीलों**

उत्तर - (B) नागरिकों

प्रश्न 13 – कौन-सा कानून अधिकारों को लागू करने, अथवा उनके उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने तथा मुकदमा करने के तंत्र का निर्धारित करता है?

(A) आपराधिक कानून **(B) नागरिक कानून**

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(C) प्रक्रियात्मक कानून **(D) अधिष्ठायी कानून**

उत्तर - (C) प्रक्रियात्मक कानून

प्रश्न 14 - अधिष्ठायी कानून एक _____ ।

(A) संवैधानिक कानून है।

(B) कार्रवाई कानून है।

(C) कर्मचारियों को नियमित करने का कानून है।

(D) गिरफ्तार करने के तंत्र को देने वाला कानून है।

उत्तर – (A) संवैधानिक कानून है।

प्रश्न 15 – 'अपील करने का अधिकार' किस कानून के अन्तर्गत मिलता है?

(A) प्रक्रियात्मक कानून **(B) अधिष्ठायी कानून**

(C) संवैधानिक कानून **(D) उपरोक्त में से कोई नहीं**

उत्तर – (A) प्रक्रियात्मक कानून

प्रश्न 16 – निम्नलिखित में से किस को अधिष्ठायी आपराधिक कानून के अन्तर्गत परिभाषित नहीं किया जाता ?

(A) हत्या **(B) डकैती**

(C) विवाह **(D) बलात्कार**

उत्तर – (C) विवाह

प्रश्न 17 – ए.डी.आर. (ADR) का सही विस्तृत रूप चुनिए :

(A) अनअदर डिस्प्यूट रिजोलुशन **(B) आल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोलुशन**

(C) आथोराईज्ड डिस्प्यूट रेफरेन्स **(D) आल्टरनेट डिस्प्यूट रिमूवल**

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

उत्तर – (B) आल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोलुशन

प्रश्न 18 – सही विकल्प चुनिए :

निम्नलिखित में से किसके निर्णय के विरुद्ध अपील करने की अनुमति नहीं है?

(A) लोक अदालत

(B) औपचारिक न्यायालय

(C) सरकारी विभाग

(D) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर – (A) लोक अदालत

प्रश्न 19 – निम्नलिखित में से कौन सा कथन 'भारत के संविधान' के बारे में 'सत्य' है?

(A) इसको न्यायविदों के एक पेनल ने निर्मित किया था।

(B) इसको 24 नवम्बर 1949 को अंगीकार किया गया था।

(C) डॉ. भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा के अध्यक्ष थे।

(D) संविधान में ऐसे कानून और नियम हैं जिनके अनुसार भारत राज्य का शासन संचालित होता है।

उत्तर – (D) संविधान में ऐसे कानून और नियम हैं जिनके अनुसार भारत राज्य का शासन संचालित होता है।

प्रश्न 20 – निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है?

(A) समानता का अधिकार

(B) स्वतंत्रता का अधिकार

(C) सम्पत्ति का अधिकार

(D) शिक्षा का अधिकार

उत्तर – (C) सम्पत्ति का अधिकार

प्रश्न 21 – रिक्त स्थानों को ठीक से भरिये :

पब्लिक और_____ कानून दोनों ही _____अथवा प्रक्रियात्मक कानून हो सकते हैं।

उत्तर – निजी ,अधिष्ठायी

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 22 – यह एक सुविदित तथ्य है कि वर्तमान न्यायिक व्यवस्था बहुत ही _____ है और किसी विवाद से जुड़ी पार्टियों को वर्षों तक_____ प्रतीक्षा करनी पड़ती है ।

उत्तर – जटिल, न्याय की

प्रश्न 23 – समझौता,_____और मुकदमेबाजी की तुलना में एक_____और आबाध्यकारी प्रक्रिया है।

उत्तर – मध्यस्थता, स्वैच्छिक

प्रश्न 24 – कालम - A में दर्ज आईटम्स को कालम B की आईटम्स के साथ सही मिलान कीजिए।

कालम – A	**कालम - B**
(a) लोक अदालत	**(i) समय और धन की बरबादी**
(b) नियमित न्यायालय	**(ii) राष्ट्रीय विधिक सेवाएँ**
	(iii) अमरीकी प्रणाली
	(iv) समय और धन की बचत

उत्तर – (a) लोक अदालत — (iv) समय और धन की बचत

(b) नियमित न्यायालय — (i) समय और धन की बरबादी

प्रश्न 25 – रिक्त स्थानों को ठीक से भरिये :

मौलिक अधिकारों को _____के किसी भी अंग द्वारा _____नहीं किया जा सकता।

उत्तर – राज्य , समाप्त

प्रश्न 26 – कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए :

(i) साधारण अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बीच कोई अन्तर नहीं है।

उत्तर – असत्य

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

(ii) मूल रूप में, भारतीय संविधान के भाग III में सात मौलिक अधिकार दर्ज थे।

उत्तर – सत्य

प्रश्न 27 – कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए :

(i) अस्पृश्यता (छुआछूत) को मिटा दिया गया है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार पर प्रतिबन्ध है।

उत्तर – सत्य

(ii) मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग IV में दर्ज हैं।

उत्तर – असत्य

प्रश्न 28 – रिक्त स्थानों को ठीक से भरिये :

राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्त _____ नहीं हैं और इनका उद्देश्य भारत को एक_____ राज्य बनाना है।

उत्तर – न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, कल्याणकारी

प्रश्न 29 – निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए :

(i) कौन राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है?

उत्तर – उपराष्ट्रपति

(ii) राज्य सभा के सदस्य किस विशेष प्रणाली के अनुसार चुने जाते हैं?

उत्तर – आनुपातिक प्रतिनिधित्व

प्रश्न 30 – रिक्त स्थानों को ठीक से भरिये :

वित्त विधेयक को केवल _____ सभा में _____की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जा सकता है।

उत्तर – लोक सभा, राष्ट्रपति

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 31 – (i) लोक सभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितने वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए?

उत्तर – 25 वर्ष

(ii) राज्य सभा का सदस्य बनने के लिए आपकी आयु कितने वर्ष की होनी चाहिए ?

उत्तर – 30 वर्ष

प्रश्न 32 – (i) संघीय सरकार और राज्यों के बीच के किसी विवाद पर कौन सा न्यायालय सुनवाई कर सकता है?

उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय

(ii) यदि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो किस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है?

उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय

विकल्प 1 – (पर्यावरण कानून और धारणीय विकास)

प्रश्न 33 - (i) ऐसी दो चीज़ों के नाम लिखिए जो पर्यावरण का भाग हैं।

उत्तर – वायु, जल

(ii) रियो सम्मेलन 1992 में किस विषय पर चर्चा हुई थी ?

उत्तर – पर्यावरण और विकास (एजेंडा 21)

प्रश्न 34 – (i) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के किसी निर्णय अथवा आदेश से पीड़ित कोई व्यक्ति किस न्यायालय में अपील करने जा सकता है?

उत्तर – सर्वोच्च न्यायालय

(ii) 1984 भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस प्रकार की गैस लीक हुई थी ?

उत्तर – मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC)

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 35 – निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए:

(a) एजेन्डा 21	**(i) प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त**
(b) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल	**(ii) भारत सरकार**
	(iii) रियो-घोषणा
	(iv) क्योटो-प्रोटोकाल

उत्तर – (a) एजेन्डा-21 - (iii) रियो-घोषणा

(b) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल - (i) प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त

विकल्प 2 – (उपभोक्ता सुरक्षा)

प्रश्न 33 – रिक्त स्थान ठीक से भरिये :

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम _____ एक ऐसा अधिनियम है जो उपभोक्ताओं के_____ की रक्षा करना है।

उत्तर – 1986 , अधिकारों

प्रश्न 34 – कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए :

(i) वस्तुओं के साथ उपहार, पुरस्कार अथवा अन्य चीजें देना 'अनुचित कारोबारी व्यवहार' नहीं है।

उत्तर – सत्य

(ii) किसी पुरानी, पुनर्निर्मित अथवा उपयोग की वस्तु को बेचना जो उपभोक्ता को स्वीकार्य है वह एक 'अनुचित कारोबारी व्यवहार' नहीं है।

उत्तर – असत्य

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 35 – निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए:

(i) जब किसी विशेष वस्तु को केवल एक ही व्यक्ति अथवा उद्यम द्वारा बेचा जाता है, तो कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है?

उत्तर – एकाधिकार

(ii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2022 को लागू करके भारत में किसको प्रोत्साहित किया गया है?

उत्तर – निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा

खंड – ख

प्रश्न 36 – हिन्दु कानून के अन्तर्गत तलाक के लिए कोई दो आधार स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – हिन्दू कानून के अंतर्गत तलाक के लिए दो प्रमुख आधार हैं:

1. **आपसी सहमति –** पति और पत्नी दोनों की सहमति से विवाह समाप्त किया जा सकता है।
2. **दुराचार –** यदि पति या पत्नी ने वैवाहिक शपथ का उल्लंघन करते हुए परस्त्री/परपुरुष के साथ संबंध बनाए, तो यह तलाक का आधार बनता है।

प्रश्न 37 – किसी अपराध के लिए कौन सी दो परिस्थितियों को आवश्यक माना गया है?

उत्तर – किसी अपराध के लिए दो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं:

1. **अपराध करना** – किसी गलत काम को करना जरूरी है।
2. **दोष भावना** – अपराध करने वाले में जानबूझकर या लापरवाही से अपराध करने की मानसिक स्थिति होनी चाहिए।

अथवा

प्रश्न 37 – आपराधिक कानून के अन्तर्गत किन्हीं चार बचावों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर – आपराधिक कानून में चार बचाव हैं:

1. **स्वयं रक्षा** – अपने आप को बचाना।
2. **मानसिक रोग** – मानसिक रोग के कारण अपराध न समझ पाना।
3. **अनजाने में करना** – गलती से अपराध करना।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

4. **अनुबंध के तहत अनुमति** – जिसकी सहमति से किया गया, वह अपराध नहीं माना जाता।

प्रश्न 38 – निजी कानून का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर – निजी कानून वह कानून है जो व्यक्तियों के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह अधिकारों और कर्तव्यों को बताता है तथा विवादों को सुलझाने का उपाय भी देता है।

अथवा

प्रश्न 38 – सार्वजनिक (जन) कानून का अर्थ स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर – सार्वजनिक (जन) कानून वह कानून है जो राज्य और जनता के बीच संबंधों को नियंत्रित करता है। यह सरकार की जिम्मेदारियों को निर्धारित करता है और जनता के राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को बताता है।

प्रश्न 39 – प्ली बार्गेनिंग के लाभों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – प्ली बार्गेनिंग में अपराधी और अदालत समझौता करते हैं। इससे समय बचता है, अदालत का काम आसान होता है और विवाद जल्दी हल हो जाता है। अपराधी को कम सजा मिल सकती है और न्याय प्रक्रिया सरल बनती है।

प्रश्न 40 – संसद की विधायी शक्तियों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – संसद के पास कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति होती है। यह देश में नए कानून बना सकती है, पुराने कानूनों में बदलाव कर सकती है और आवश्यकतानुसार कानूनों को निरस्त कर सकती है। संसद की विधायी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच बटवारे के आधार पर होती हैं।

विकल्प 1 (पर्यावरण और धारणीय विकास)

प्रश्न 41 – क्योटो प्रोटोकॉल की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों को कम करना और जलवायु परिवर्तन रोकना है। इसके तहत विकसित देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य दिए गए हैं।

विकल्प 2 (उपभोक्ता सुरक्षा)

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

प्रश्न 41 – 'उपभोक्ता निवारण ' का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – उपभोक्ता निवारण का अर्थ है उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और उनके हित में शिकायतों का समाधान करना। यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता बेईमानी, धोखाधड़ी या खराब उत्पादों से बच सकें और न्याय पाएं।

प्रश्न 42 – 'मिश्रित कानून प्रणाली' की किन्हीं दो महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – मिश्रित कानून प्रणाली में दो या दो से अधिक कानूनों का मिश्रण होता है, जैसे कि हिन्दू, मुस्लिम और ब्रिटिश कानून। इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं:

1. **अलग-अलग स्रोतों का संयोजन –** इसमें परंपरागत कानून और आधुनिक कानून दोनों शामिल होते हैं।
2. **लचीली न्याय व्यवस्था –** विभिन्न कानूनों के अनुसार न्याय देने में लचीलापन मिलता है और विवादों को आसानी से सुलझाया जा सकता है।

अथवा

प्रश्न 42 – किसी मुस्लिम विवाह की वैधता के लिए दो अनिवार्यताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – किसी मुस्लिम विवाह की वैधता के लिए दो अनिवार्यताएँ:

1. **सहमति :** किसी भी मुस्लिम विवाह के लिए यह जरूरी है कि दोनों पक्षों की पूरी और स्वतंत्र सहमति हो। यदि लड़का या लड़की की सहमति नहीं है, तो विवाह अवैध माना जाएगा। यह इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि विवाह दबाव या जबरदस्ती के बिना संपन्न हो।
2. **महर :** शादी के समय वर द्वारा दुल्हन को धन, संपत्ति या किसी मूल्यवान वस्तु देना अनिवार्य है। यह दुल्हन के अधिकार और सुरक्षा का प्रतीक है। महर का भुगतान तुरंत या बाद में किया जा सकता है, लेकिन इसकी घोषणा और सहमति विवाह का जरूरी हिस्सा है।

प्रश्न 43 – संवैधानिक उपचारों के अधिकार के महत्व का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की **"आत्मा और हृदय"** माना गया है। इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यह नागरिकों को उनके **मौलिक अधिकारों की सुरक्षा** सुनिश्चित करता है। यदि मौलिक अधिकार केवल लिखित हों लेकिन उनका पालन न हो, तो वे व्यर्थ हैं। संवैधानिक उपचारों के तहत न्यायालय **रिट** (जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध) जारी कर सकता है, जिससे सरकार की मनमानी पर रोक लगती है और नागरिक सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

अथवा

प्रश्न 43 – आपराधिक कानून के किन्हीं दो सिद्धान्तों का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर – आपराधिक कानून के किन्हीं दो सिद्धान्तों का विश्लेषण कीजिए। आपराधिक न्याय प्रणाली के दो आधारभूत सिद्धान्त हैं:

1. **निर्दोषिता की धारणा :** कानून की नज़र में हर व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि न्यायालय द्वारा उसे दोषी सिद्ध न कर दिया जाए।
2. **सबूत का भार :** आरोपी को अपनी बेगुनाही साबित नहीं करनी होती, बल्कि अभियोजन पक्ष (Prosecution) को यह साबित करना होता है कि आरोपी ने अपराध किया है, वह भी संदेह से परे।

प्रश्न 44 – प्रक्रियात्मक कानून के अन्तर्गत आने वाली किन्हीं चार कार्रवाईयों को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – प्रक्रियात्मक कानून यह तय करता है कि न्याय कैसे मिलेगा। इसकी चार मुख्य कार्रवाईयाँ हैं:

1. **प्राथमिकी (FIR) दर्ज करना :** किसी अपराध की सूचना पुलिस को देना कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत है।
2. **अन्वेषण (Investigation) :** पुलिस द्वारा सबूत इकट्ठा करना, गवाहों के बयान लेना और आरोपी को गिरफ्तार करना।
3. **विचारण (Trial) :** अदालत में मुकदमा चलना, जहाँ दोनों पक्ष अपने सबूत और दलीलें पेश करते हैं।
4. **निर्णय और अपील (Judgment & Appeal) :** अदालत द्वारा फैसला सुनाना और उस फैसले से असंतुष्ट होने पर ऊपरी अदालत में अपील दायर करना।

अथवा

प्रश्न 44 – संवैधानिक कानून के कोई चार कार्य स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – संवैधानिक कानून देश का सर्वोच्च कानून है। इसके चार प्रमुख कार्य हैं:

1. **सरकार का ढांचा तय करना :** यह विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का गठन और उनकी संरचना निर्धारित करता है।
2. **शक्तियों का वितरण :** यह केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा करता है ताकि संघर्ष न हो।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

3. **शक्तियों पर नियंत्रण :** यह सरकार के अंगों पर रोक लगाता है ताकि कोई भी अंग तानाशाह न बन सके।
4. **अधिकारों की रक्षा :** यह नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।

प्रश्न 45 – किन्हीं चार मौलिक अधिकारों का वर्णन कीजिए।

उत्तर – भारतीय संविधान के भाग III में छह मौलिक अधिकार हैं, उनमें से चार निम्नलिखित हैं:

1. **समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) :** कानून के समक्ष सभी समान हैं और धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
2. **स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) :** इसमें भाषण, अभिव्यक्ति, संघ बनाने, घूमने-फिरने और कोई भी पेशा चुनने की स्वतंत्रता शामिल है।
3. **शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) :** यह मानव तस्करी, बेगार और कारखानों में बच्चों के काम करने पर रोक लगाता है।
4. **धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) :** प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता है।

प्रश्न 46 – लोक सभा अध्यक्ष की किन्हीं चार शक्तियों की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – लोक सभा अध्यक्ष सदन का प्रमुख पीठासीन अधिकारी होता है। उसकी चार शक्तियाँ हैं:

1. **सदन का संचालन :** वह सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है, अनुशासन बनाए रखता है और कार्यवाही को नियमानुसार चलाता है।
2. **धन विधेयक का निर्णय :** कोई विधेयक 'धन विधेयक' है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही करता है।
3. **अनुशासनात्मक शक्ति :** यदि कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में बाधा डालता है, तो अध्यक्ष उसे निलंबित कर सकता है।
4. **निर्णायक मत :** सामान्यतः अध्यक्ष मतदान नहीं करता, लेकिन यदि पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएं, तो वह निर्णायक मत देता है।

प्रश्न 47 – छः प्रकार के ऐसे लोगों का वर्णन कीजिए जिन्हें मुफ्त विधिक सेवाएँ प्राप्त करने का अधिकार है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

उत्तर – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि गरीबी या किसी अन्य अक्षमता के कारण कोई भी नागरिक न्याय से वंचित न रहे। निम्नलिखित छः प्रकार के लोग मुफ्त कानूनी सलाह और वकील पाने के हकदार हैं:

1. **अनुसूचित जाति/जनजाति (SC/ST) के सदस्य :** इस वर्ग का कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी आय कितनी भी हो, मुफ्त सेवा का हकदार है।
2. **महिलाएं और बच्चे :** सभी महिलाएं और बच्चे अपनी सुरक्षा और अधिकारों के लिए मुफ्त कानूनी मदद ले सकते हैं।
3. **मानव तस्करी या बेगार के पीड़ित :** ऐसे लोग जिन्हें जबरन काम कराया गया हो या देह व्यापार में धकेला गया हो।
4. **दिव्यांग व्यक्ति :** अंधापन, कुष्ठ रोग, बहरापन या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति।
5. **बड़ी आपदाओं के पीड़ित :** जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप या औद्योगिक आपदा (जैसे भोपाल गैस कांड) के पीड़ित लोग।
6. **हिरासत में बंद व्यक्ति :** कोई भी व्यक्ति जो पुलिस हिरासत या जेल में बंद है, उसे मुफ्त वकील पाने का अधिकार है।

अथवा

प्रश्न 47 – उस अधिनियम का नाम लिखिए जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय और राज्य सरकारें जरूरतमंद और गरीब लोगों को निःशुल्क (मुफ्त) विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकरण गठित कर सकती हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित सभी प्राधिकरणों के नाम लिखिए।

उत्तर – जरूरतमंद और गरीब लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए संसद ने **"विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987"**पारित किया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्राधिकरण: न्याय को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए चार स्तरों पर संस्थाएँ बनाई हैं:

1. **राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) :** यह राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च संस्था है। भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। यह नीतियाँ बनाता है।
2. **राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA) :** प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में यह संस्था कार्य करती है। यह NALSA की नीतियों को राज्य में लागू करती है।
3. **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) :** हर जिले में यह संस्था होती है जिसका अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होता है। यह जिले में कानूनी सहायता शिविर और लोक अदालतें आयोजित करता है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

4. **तालुका विधिक सेवा समिति (Taluka Legal Services Committee) :** यह तहसील या तालुका स्तर पर कार्य करती है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को कानूनी मदद मिल सके।

प्रश्न 48 – स्वतंत्रता के अधिकार अन्तर्गत दी गई (प्रत्याभूत) किन्हीं छः स्वतंत्रताओं को स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – संविधान का अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को छह लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएँ प्रदान करता है, जो व्यक्ति के विकास के लिए अनिवार्य हैं:

1. **भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :** हर नागरिक को अपने विचार बोलने, लिखने, छापने या चित्र द्वारा व्यक्त करने का अधिकार है। प्रेस की आज़ादी भी इसी में शामिल है।
2. **शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता :** नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से सभा करने, जुलूस निकालने या बैठक करने का अधिकार है।
3. **संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता :** लोग अपनी मर्जी से राजनीतिक दल, ट्रेड यूनियन, क्लब या सहकारी समितियाँ बना सकते हैं।
4. **घूमने-फिरने की स्वतंत्रता :** भारत का कोई भी नागरिक देश के किसी भी हिस्से में बिना किसी रोक-टोक के आ-जा सकता है सिवाय कुछ प्रतिबंधित जनजातीय क्षेत्रों के।
5. **निवास की स्वतंत्रता :** नागरिक भारत के किसी भी भाग में बसने या घर बनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
6. **वृत्ति या व्यवसाय की स्वतंत्रता :** कोई भी नागरिक अपनी पसंद का कोई भी पेशा, व्यापार या नौकरी कर सकता है।

अथवा

प्रश्न 48 – मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों के बीच कोई चार अन्तर स्पष्ट कीजिए।

उत्तर – मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच अंतर:

1. **प्रभाव :** मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं।
2. **लक्ष्य :** मौलिक अधिकार का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य समाज और राष्ट्र का कल्याण सुनिश्चित करना है।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

3. **प्रकृति :** मौलिक अधिकार निजी और व्यक्तिवादी हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक हैं।
4. **संपूर्णता :** मौलिक अधिकार संविधान के भाग III में आते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग IV में आते हैं।

मौलिक अधिकार नागरिकों के सीधे अधिकार हैं और लागू किए जा सकते हैं, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए मार्गदर्शक हैं और अदालत में लागू नहीं किए जा सकते।

विकल्प 1 – (पर्यावरण कानून और धारणीय विकास)

प्रश्न 49 – धारणीय विकास की किन्हीं छः आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर – धारणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करे। इसकी आवश्यकताएँ:

1. **संसाधनों का संरक्षण :** कोयला, पेट्रोल जैसे प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। इन्हें भावी पीढ़ी के लिए बचाने हेतु इनका विवेकपूर्ण उपयोग जरूरी है।
2. **प्रदूषण नियंत्रण :** अंधाधुंध विकास से वायु और जल प्रदूषित हो रहा है। धारणीय विकास स्वच्छ तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देता है।
3. **जैव विविधता की रक्षा :** पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न जीव-जंतुओं और पेड़-पौधों को विलुप्त होने से बचाना आवश्यक है।
4. **जलवायु परिवर्तन से बचाव :** ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं से निपटने के लिए पर्यावरण के अनुकूल जीवनशैली अपनाना जरूरी है।
5. **गरीबी उन्मूलन :** धारणीय विकास केवल अमीरों के लिए नहीं है, इसका लक्ष्य संसाधनों का समान वितरण कर गरीबों का जीवन स्तर सुधारना है।
6. **अंतर-पीढ़ीगत समानता :** यह एक नैतिक आवश्यकता है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को एक रहने योग्य और स्वस्थ पृथ्वी सौंप कर जाएं।

विकल्प 2 – (उपभोक्ता सुरक्षा)

प्रश्न 49 – किन्हीं छः अनुचित कारोबारी व्यवहारों को स्पष्ट कीजिए।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

उत्तर – उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत, मुनाफा कमाने के लिए व्यापारियों द्वारा अपनाए जाने वाले गलत तरीके अनुचित व्यापार व्यवहार कहलाते हैं:

1. **मिथ्या प्रचार :** विज्ञापन में उत्पाद की गुणवत्ता, मात्रा या उपयोगिता के बारे में झूठे दावे करना।
2. **भ्रामक वारंटी/गारंटी :** उत्पाद पर ऐसी गारंटी देना जो बिना उचित परीक्षण के दी गई हो या जिसे पूरा करने का इरादा न हो।
3. **जमाखोरी :** बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने और दाम बढ़ाने के लिए सामान को छिपाकर रखना या नष्ट करना।
4. **नकली सामान :** ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली या घटिया सामान बेचना जो उपभोक्ता के लिए खतरनाक हो सकता है।
5. **उपहार का लालच :** बिक्री बढ़ाने के लिए लॉटरी या इनाम का लालच देना और बाद में परिणाम में हेराफेरी करना।
6. **सुरक्षा मानकों की अनदेखी :** ऐसे उत्पाद बेचना जो सुरक्षा मानकों पर खरे नहीं उतरते (जैसे बिना ।S। मार्क के खराब हेलमेट या कुकर बेचना)।

All Rights Reserved © Manish Verma (MVS Foundation), for more Notes visit https://www.mvsfoundation.in/

Thank you!

We hope you found this material helpful. We wish you the very best for your examination.

Strive for Excellence – Your Path to Success